आंध्र प्रदेश राज्य

बनाम

के. श्रीनिवासुलु रेड्डी और अन्य

18 दिसंबर, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 34,302 और 326- अभियुक्त और मृतक के बीच विवाद और सिविल मुकदमेबाजी-अभियुक्त ने चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति में मृतक पर धारदार हथियारों से हमला किया और उन्हें धमकी दी कि मृतक के शरीर पर पचास चोटें आईं-उच्च न्यायालय ने सदमे और रक्तस्राव के कारण मौत का उल्लेख करते हुए मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि किस चोट के कारण मौत हुई और किस आरोपी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इस बारे में संदेह पर धारा 302 से धारा 326 में दोषसिद्धि को बदल दिया-आयोजित, विचारण अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 302 को दोषसिद्धि में परिवर्तन करने में उचित रूप से लागू नहीं किया गया-सामान्य इरादा स्पष्ट रूप से अभियुक्त के आचरण और अंधाधुंध हमलों के तरीके से उचित संदेह से परे माना और साबित किया गया।

आपराधिक मुकदमा-साक्ष्य की प्रशंसा-चश्मदीद गवाह-स्वतंत्र गवाहों पर बचाव पक्ष द्वारा "संयोग गवाह" के रूप में हमला किया गया- माना गया, ऐसे गवाहों के साक्ष्य को संदिग्ध के रूप में निहित नहीं किया जा सकता है और उनकी उपस्थिति इस तरह के विवरण से घटना के स्थान पर संदिग्ध हो सकती है, -हत्याएं पूर्व सूचना के साथ नहीं की गई गवाहों को उनकी उपस्थिति का अनुरोध कर रहे है - आयोजित तथ्यों में, कहा गया है कि गवाहों ने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया है-धारा 34,302 और 326।

अभियोजन का मामला यह था कि वी और उनकी पत्नी बी को कोई समस्या नहीं थी और उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे और वे अलग रह रहे थे और वी ,बी को भरण-पोषण का भुगतान कर रहा था. वी अपनी संपत्तियों को अपनी बहन के बेटों, डी और पी डब्लू- 1 को देना चाहता था, जबकि बी चाहता था कि वी, अभियुक्त ए-1 और ए-2 को संपत्ति दे जो उसकी बहन के बेटे थे। हालांकि, वी ने अपनी सभी संपत्तियों को डी और पीडब्लू-1 के पक्ष में वसीयत कर दिया और वे उनकी मृत्यु के बाद संपत्तियों की देखभाल कर रहे थे और बी को उसकी मृत्यु तक उनके लिए रखरखाव का भुगतान कर रहे थे।अभियुक्त को डी और पीडब्लू-1 के खिलाफ दुर्भावना थी और विवाद उत्पन्न हुए जिससे उनके बीच विभिन्न सिविल मुकदमे हुए। डी और पीडब्लू-1 ने डिक्री प्राप्त की और वी की संपत्तियों पर

कब्जा कर लिया। लंबे समय तक मुकदमेबाजी के कारण आरोपी लगभग गरीब हो गया और सिविल मुकदमे से परेशान हो गया, आरोपी ए-3 और ए-4 के साथ आपराधिक मामले में शामिल हो गया डी और पीडब्लू-1 की हत्या की साजिश रची । घटना के दिन आरोपी ने डी पर पनकट्टी और कुल्हाड़ी से हमला किया, उसका पीछा किया और और अंधाधुंध हमला किया। पीडब्लू. 1, 2, 3 और 5 ने अभियुक्तों से अनुरोध किया कि वे डी को न मारें लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पीडब्लू को भी दरकिनार कर दिया। 4 बी और 9 जिन्होंने आरोपियों को डी को हैक करने से रोकने की कोशिश की और उन्हें और वहां इकट्ठा हुए अन्य लोगों को धमकाया।

आरोपी ने डी के शरीर पर पचास चोटें पहुंचाईं, जिसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि डी की मृत्यु कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी सी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया लेकिन ए-3 और ए-4 को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि आईपीसी की धारा 120-बी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। आरोपी द्वारा की गई अपील में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 302 से धारा 326 में बदल दिया कि इसमें संदेह था कि किस आरोपी द्वारा कौन सी

चोट पहुंचाई गई थी और किस चोट के परिणामस्वरूप अंततः मृतक की मृत्यु हुई। इसलिए यह राज्य द्वारा अपील है।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है उच्च न्यायालय आई. पी. सी. की धारा 326 में दोषसिद्धि को बदलना उचित नहीं था; और यह कि आई. पी. सी. की धारा 34 पूरी तरह से लागू थी।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि हमले करने में कोई सामान्य इरादा दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था और इसलिए आईपीसी की धारा 302 का कोई उपयोग नहीं हुआ; कि पीडब्लू 4 और 9 मौका गवाह थे जिन्होंने यह नहीं बताया कि वे कथित घटना स्थल पर कैसे हुए। ; उस दोषसिद्धि को आईपीसी की धारा 326 में सही रूप से बदल दिया गया है क्योंकि किसी विशेष अपराधी को कोई विशेष चोट नहीं पहुंचाई जा सकती; और धारा 34 आईपीसी का कोई अनुप्रयोग नहीं था।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1. अभियुक्त के पहले और बाद के आचरण से अंधाधुंध हमलों की घटना और तरीके से एक सामान्य इरादा स्पष्ट रूप से माना जाता है और संदेह से परे साबित होता है। अन्यथा भी, अभियुक्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को देखते हुए, चोटें बड़ी संख्या में और महत्वपूर्ण हिस्सों पर होने के कारण, आईपीसी की धारा 302 को ट्रायल कोर्ट द्वारा सही ढंग से

लागू किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को बदलना उचित नहीं था। (1057-बी-सी)

विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर (1956) एस. सी. 116 और धन्ना आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर (1996) एससी 2478, पर भरोसा किया।

2.1. हत्या के मुकदमे में स्वतंत्र गवाहों को "मौका गवाह" के रूप में वर्णित करके यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साक्ष्य संदिग्ध हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। हत्याएं नहीं हैं गवाहों को पूर्व सूचना के साथ प्रतिबद्ध; उनकी उपस्थिति का आग्रह करना। यदि किसी आवास गृह में हत्या की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीर ही गवाह होंगे। उनके साक्ष्यों को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता या संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता कि वे महज "संयोगी गवाह" हैं। (1058-बी-सी)

2.2 पीडब्लू 4 और 9 के आकस्मिक गवाह होने की आलोचना बिना किसी आधार के है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वे घटनास्थल पर कैसे पहुंचे और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त गवाह स्वतंत्र गवाह

थे। गवाहों को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनकी किसी अभियुक्त से कोई दुश्मनी थी। (1057-एच; 1058-ए-बी)

3. विचारण न्यायालय का फैसला बहाल किया गया है। उत्तरदाताओं को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उन्हें शेष सजा काटने के लिए हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। (1058-एफ}

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 897/ 1997

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 28.11.96 निर्णय और आदेश से आपराधिक अपील संख्या 626/1995

श्रीमती के. अमरेश्वरी, बी. रमण मूर्ति और गुंटूर प्रभाकर अपीलार्थी के लिए।

जी. रामकृष्ण प्रसाद, मो. वसी खान और डी. महेश बाबू उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति अरिजीत पसायत -

विवादित निर्णय द्वारा एक प्रभाग आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ ने उत्तरदाताओं (इसके बाद 'अभियुक्त' के रूप में संदर्भित) की दोषसिद्धि को धारा 302 से बदल दिया। भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') से आई. पी. सी. की धारा 326 तक। आंध्र प्रदेश राज्य ने फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है।

विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले से सामने आए पृष्ठभूमि तथ्य अनिवार्य रूप से इस प्रकार हैं:

आरोपी पामारू गांव के रहने वाले हैं और वे करीबी सहयोगी हैं। ए-1 और ए-2 भाई हैं। ए-4 ए-2 की पत्नी है और ए-3 पामारू गाँव के सरपंच है एक दांडीपति गंगी रेड्डी (जिसे इसके बाद मृतक के रूप में संदर्भित किया गया है) भी पामारू का निवासी था। पीडब्लू-1 लक्ष्मी रेड्डी उनके भाई हैं, पीडब्लू-2 चंद्र शेखर रेड्डी उनके बेटे हैं। एक बोम्मारेड्डी वेंकट रेड्डी पीडब्लू-1 लक्ष्मी रेड्डी के मामा हैं और मृतक ए-1 और ए-2 एक सुरम्मा के बेटे हैं, जो बोम्मारेड्डी वेंकट रेड्डी की पत्नी की बहन है, जिसका नाम बुलेम्मा है, जिसके अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और उन्हें कोई समस्या नहीं थी।

बोम्मारेड्डी वेंकट रेड्डी के पास 18 एकड़ ज़मीन और घर थे। बुल्लेम्मा ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पति को अपनी संपत्ति अपनी बहन के बेटों यानी ए-1 और ए-2 को दे देनी चाहिए; लेकिन वेंकट

रेड्डी पीडब्लू-। और मृतक, जो उसकी बहन के बेटे थे, को संपत्ति देने के मूड में थे, क्योंकि उनके मन में उनके प्रति अधिक स्नेह और प्यार था। इन मतभेदों के कारण, बुल्लेम्मा और वेंकट रेड्डी अलग हो गए थे और वेंकट रेड्डी न्यायालय के आदेश के अनुसार अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहे थे। इसके बाद वेंकट रेड्डी ने अपनी संपत्ति पीडब्लू-1 लक्ष्मी रेड्डी और मृतक को सौंपने के लिए एक 'वसीयत' निष्पादित की। वेंकट रेड्डी की मृत्यु के बाद, मृतक और पीडब्लू-1 संपत्तियों की देखभाल कर रहे थे और बुल्लेम्मा को उसके मरने तक भरण-पोषण का भुगतान कर रहे थे। ए-1 और ए-2 मृतक और पीडब्लू-1 के प्रति द्वेष रखते थे, क्योंकि वेंकट रेड्डी ने उन्हें कोई संपत्ति नहीं दी थी। इसलिए, विवाद उत्पन्न हुए और सिविल मुकदमा दायर किया गया और घटना की तारीख से लगभग तीन साल पहले पीडब्लू -1 और मृतक के पक्ष में फैसला सुनाया गया और उन्होंने वेंकट रेड्डी की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। उक्त डिक्री के खिलाफ, ए-2 ने उच्च न्यायालय में अपील की और संबंधित समय पर मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था। मृतक और पीडब्लू-। ने ओएस 138/86 में गुडीवाड़ा के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में एक और मुकदमा दायर किया। और इस मामले में घटना से तीन महीने पहले, न्यायालय ने पीडब्लू- । और मृतक के पक्ष में एक डिक्री पारित की। इस प्रकार, ए-1 और ए-2 की नाराजगी और अधिक तीव्र हो गई। ए-3, जो पमारू का सरपंच था, की कथित तौर पर बुल्लेम्मा की छोटी बहन के साथ अवैध

अंतरंगता थी। इसलिए, उसने वेंकट रेड्डी की पत्नी और ए-1 और ए-2 का समर्थन किया। लंबे समय तक चली इन मुक़दमों के कारण, A-1 और A-2 लगभग कंगाल हो गए।

सिविल अदालत के मुकदमों से परेशान होकर और मृतक और पीडब्लू-1 के पक्ष में अदालत के आदेशों के कारण, अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक को मारने की योजना बनाई। घटना की तारीख से लगभग एक सप्ताह पहले, सभी आरोपी ए-2 के घर में कई बार इकट्ठा हुआ और मृतक की हत्या की आपराधिक साजिश रची और ए-3 ने यह भी कहा कि वह हैदराबाद जाएगा और वहां रहेगा और ए-1 और ए-2 को मृतक के लौटने से पहले उसकी हत्या करने का निर्देश दिया। ए-4 ने ए-1 और ए-2 को मृतक की हत्या करने का भी निर्देश दिया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी है और गरीब हो गए हैं।

3.9.1992 को, वह मनहूस दिन, ए-1 और ए-2 अपनी आपराधिक साजिश के तहत पमारू में नए पुल के पास इंतजार कर रहे थे। जबकि A-1 ने नाभि के पास एक पेनकट्टी को छुपाया और हथियार को अपनी शर्ट और तौलिये से छुपाया, A-2 ने एक कुल्हाड़ी को नाभि के पास और अपनी शर्ट और तौलिये से छिपाकर छुपाया। ए-1 ढलान पर एक दुकान के पास इंतजार कर रहा था और ए-2 न्यू ब्रिज के पास सड़क पर इंतजार कर रहा था, उन्होंने मृतक को लगभग 8.45 बजे गांव से केंद्र की ओर साइकिल

पर आते हुए पाया और दोनों आरोपियों ने उस पर पेनकट्टी से हमला किया। और कुल्हाड़ी. ए-1 ने उसके सिर पर पेनकट्टी से वार किया और ए-2 ने भी उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और मृतक अपनी साइकिल से पुल की दीवार के किनारे गिर गया। फिर मृतक ने केंद्र की ओर भागने की कोशिश की। ए-1 और ए-2 ने उसका पीछा किया और पेनाकट्टी और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। फिर मृतक ढलान में गिर गया। ए-1 और ए-2 ने मृतक पर अंधाधुंध हमला किया। पीडब्लू 1,2,3 और 5 अर्थात लक्ष्मी रेड्डी, चंद्रशेखर रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी और वेंकटरामा रेड्डी ने अभियुक्तों से मृतक को न मारने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब पीडब्ल्यू.-9 शिवा रेड्डी और पीडब्ल्यू.-4 नानचरय्या ने आरोपी को मृतक को हत्या करने से रोकने की कोशिश की। अभियुक्तों ने उन्हें दरकिनार कर दिया और साइकिल को नहर में फेंक दिया और धमकी दी उपरोक्त दो व्यक्ति और अन्य व्यक्ति जो वहाँ एकत्र हुए थे। अभियुक्त ने मृतक के शरीर पर लगभग पचास घाव किए हथियारों के साथ घटना स्थल छोड़ दिया। मृतक को अस्पताल ले जाया गया, पीडब्लू-7 चिकित्सा अधिकारी ने गंगी रेड्डी की जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में चिकित्सा अधिकारी ने मृतक के शरीर का शव परीक्षण करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मौत सदमे और रक्तस्राव से हुई है, कई चोटों के कारण। लगभग 9:45 बजे पीडब्लू-1 ने पुलिस उप-निरीक्षक, पामारू को एक रिपोर्ट दी, जिन्होंने दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत पामारू पुलिस स्टेशन के आपराधिक मामला संख्या 89/92 के रूप में मामला दर्ज किया। पुलिस उप-निरीक्षक ने मध्यस्थों (पीडब्लू 9 और 11) और एक अन्य की उपस्थिति में अपराध स्थल का दौरा किया , खून से सनी पलमायरा के पत्ते और खून से सनी मिट्टी जब्त की और पंचायतदार पीडब्लू-11 और एक के. रामा राव की उपस्थिति में शव की जांच की। दर्ज कराई गई जानकारी के आधार पर जांच की गई। चार अभियुक्त व्यक्तियों में से ए-1 और ए-2 पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था, जबकि चारों अभियुक्तों पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था।

विचारण न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा किया और आयोजित किया गया। कि जहाँ तक ए-1 और ए-2 का संबंध है, आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए थे। लेकिन लोक अभियोजक द्वारा दिए गए इस बयान पर कार्यवाही करते हुए कि ए-3 और ए-4 के खिलाफ कोई निश्चित सामग्री नहीं थी, उन्हें बरी करने का निर्देश दिया। चारों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध का भी दोषी नहीं ठहराया गया था।

दोषी अभियुक्तों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों का प्राथमिक रुख यह था कि लविंग द्वारा साक्ष्य के एक हिस्से को खारिज करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू 2, 4, 6 और 9 के साक्ष्य पर विश्वास करने में गलती की। हालांकि पुलिस स्टेशन पास में स्थित था, शिकायत दर्ज करने में देरी हुई और उसे ठीक से समझाया नहीं गया। चूंकि पोस्टमार्टम में मृतक के शरीर पर बड़ी संख्या में चोटें पाई गईं, इसलिए यह बेहद असंभव है कि मृतक को पेनकट्टी और कुल्हाड़ी से काटने के आरोपी दो आरोपी इतनी बड़ी संख्या में चोटों का कारण बन सकते हैं।

चोटों में से एक को कुंद हथियार के कारण बताया गया था और किसी भी गवाह द्वारा कुंद हथियार के उपयोग के बारे में बात नहीं की गई थी। नेत्र साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। राज्य का रुख उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि ट्रायल कोर्ट ने ए-1 और ए-2 के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए सबूतों का उचित विश्लेषण किया था। चूँकि सबूत स्वीकार्य और भरोसेमंद थे, ट्रायल कोर्ट ने उस पर सही कार्रवाई की। वहाँ वास्तव में एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई। चोट संख्या I0 दर्ज करने वाले डॉक्टर द्वारा की गई टिप्पणियाँ काल्पनिक थीं। इसमें यह नहीं कहा गया कि चोट आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से नहीं हुई होगी। उच्च न्यायालय ने स्वीकार

किया कि चोटों और इस्तेमाल किए गए हथियारों की कथित संख्या के बारे में पुष्टि हुई थी। मृत्यु का कारण जो हत्या थी हमलों के कारण। इसलिए, उच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण अदालत के तर्क और निष्कर्ष न्यायसंगत और सही थे। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में चोटें पाई गईं और वे महत्वपूर्ण हिस्सों पर थीं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि कौन सी चोट किस आरोपी के कारण हुई थी और कौन सी चोट अंततः मृतक की मौत का कारण बनी। इस परिसर में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आई. पी. सी. की धारा 302 लागू नहीं थी। यह भी देखा गया कि अपराध करने में ए-1 और ए-2 की भागीदारी स्थापित की गई थी, लेकिन चूंकि इस बात पर संदेह था कि किस चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, इसलिए लागू किया जाने वाला उचित प्रावधान आई. पी. सी. की धारा 326 है, जिसके लिए तदनुसार पांच साल का कठोर कारावास लगाया गया था।

अपील के समर्थन में, सुश्री के. अमरेश्वरी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत है। अभिलेख पर साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्ति घातक हथियारों से लैस थे, उन्होंने मृतक पर ज्यादातर महत्वपूर्ण भागों पर अंधाधुंध हमला किया और लगभग 50 चोटे पहुंचाईं। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय ने

दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 326 में बदलना उचित नहीं माना। किसी भी स्थिति में, धारा 34 पूरी तरह से लागू थी।

जवाब में, अभियुक्त उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हमला करने में किसी भी सामान्य इरादे को दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था और जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही देखा, आई. पी. सी. की धारा 302 का कोई अनुप्रयोग नहीं था। जाँच के दौरान दिए गए अपने बयान को फिर से दर्ज करने वाले कुछ गवाहों के साक्ष्य के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया था कि दो व्यक्ति यानी अभियुक्त ए-1 और ए-2 जिनकी शारीरिक संरचना कमजोर थी, गवाहों द्वारा काफी बड़ी संख्या में विरोध किया गया और जो शारीरिक रूप से सुगठित थे। यह तथ्य कि ऐसा नहीं हुआ, यह दर्शाता है कि वे मौजूद नहीं थे। किसी भी मामले में, अपराध का कोई उद्देश्य नहीं है क्योंकि अंततः पीडब्लू 1 और 2 को हत्या से लाभ हुआ होगा। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि किसी विशेष आरोपी को कोई विशेष चोट नहीं लगी है, इसलिए दोषसिद्धि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 326 में बदल दिया गया है और धारा 34 का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय वास्तव में वास्तविक प्रश्न पर विचार करने से चूक गया है और इसने निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि किसी विशेष गवाह को कोई विशेष चोट नहीं दी जा सकती है, इसलिए दोषसिद्धि को

आई. पी. सी. की धारा 326 में बदलना उचित तरीका होना चाहिए। इस तर्क को या तो ठोस तर्क के रूप में या आपराधिक न्यायशास्त्र के किसी भी स्थापित सिद्धांत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। घटना से पहले और बाद में अभियुक्त के आचरण और अंधाधुंध हमलों के तरीके से, एक सामान्य इरादे को स्पष्ट रूप से समझा जाता है और संदेह से परे साबित किया जाता है। अन्यथा भी, अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए हथियारों को देखते हुए, बड़ी संख्या में और महत्वपूर्ण हिस्सों पर चोटें होने के कारण, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 302 आईपीसी को सही ढंग से लागू किया गया था और उच्च न्यायालय दोषसिद्धि में बदलाव करने के लिए उचित नहीं था। दोषसिद्धि की वैधता इस तरह के आरोप के अभाव में आईपीसी की धारा 34 को लागू करने की कई मामलों में जांच की गई। विली (विलियम) स्लेनी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर(1956) एस. सी. 116 का आयोजन इस प्रकार किया गया थाः

"भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 114 और 149 वास्तविक प्रतिभागियों, सहायक तत्वों और एक सामान्य उद्देश्य या एक सामान्य इरादे से सक्रिय व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न कोणों से देखे जाने वाले आपराधिक दायित्व का प्रावधान करती है; और आरोप प्रत्यक्ष दायित्व से जुड़ा हुआ है और यह निर्दिष्ट किए बिना रचनात्मक दायित्व कि कौन सीधे

तौर पर उत्तरदायी है और किसे रचनात्मक रूप से उत्तरदायी बनाने की मांग की गई है।

ऐसी स्थिति में, अपराध के लिए आपराधिक दायित्व के विभिन्न शीर्षकों में से एक या अन्य के तहत आरोप की अनुपस्थिति को अपने आप में घातक नहीं कहा जा सकता है, और बिना किसी आरोप के मूल अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले, उसे रद्द किया जा सकता है। पूर्वाग्रह को दूर करना होगा. इस प्रकार के अधिकांश मामलों में आम तौर पर शुरू से ही साक्ष्य दिया जाता है कि उस कार्य के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था जिसके कारण अपराध हुआ और ऐसे साक्ष्य निश्चित रूप से प्रासंगिक हैं।"

उपरोक्त स्थिति को धन्ना आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर (1996) एससी 2478 में दोहराया गया था।

पीडब्लू 4 और 9 के साक्ष्यों की आलोचना की गई, जो स्वतंत्र गवाह हैं, उन्हें आकस्मिक गवाह के रूप में लेबल करके। पीडब्लू 4 और 9 के आकस्मिक गवाह होने की आलोचना भी बिना किसी आधार के है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि वे घटना स्थल पर कैसे पहुंचे और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार कर लिया है:

आरोपियों की इस दलील पर कि पीडब्लू 4 और 9 'मौका गवाह' थे, जिन्होंने यह नहीं बताया है कि वे कथित घटना स्थल पर कैसे पहुंचे, यह

ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त गवाह स्वतंत्र गवाह थे। गवाहों को इस बात का तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनकी किसी अभियुक्त से कोई दुश्मनी है। हत्या के मुकदमे में स्वतंत्र गवाहों को 'संयोगी गवाह' बताकर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके साक्ष्य संदिग्ध हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। गवाहों को उनकी उपस्थिति के लिए पूर्व सूचना देकर हत्याएं नहीं की जातीं। यदि हत्या किसी आवासीय घर में की जाती है, तो घर के निवासी स्वाभाविक गवाह होते हैं। यदि सड़क पर हत्या की जाती है, तो केवल राहगीर ही गवाह होंगे। उनके सबूतों को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता या संदेह की नजर से नहीं देखा जा सकता कि वे महज 'मौका गवाह' हैं। अभिव्यक्ति 'मौका गवाह' उन देशों से ली गई है जहां हर आदमी के घर को उसका महल माना जाता है और हर किसी के पास कहीं और या किसी अन्य व्यक्ति के महल में अपनी उपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण होना चाहिए। यह ऐसे देश में बिल्कुल अनुपयुक्त अभिव्यक्ति है जहां लोग अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करने के मामले में कम औपचारिक और अधिक अनौपचारिक होते हैं।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी-प्रतिवादियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराना उचित था और उच्च न्यायालय ने बिना किसी कानूनी आधार के दोषसिद्धि को बदल दिया। विचारण न्यायालय का फैसला बहाल कर दिया जाता है उत्तरदाताओं को

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उन्हें शेष सजा काटने के लिए हिरासत में आत्मसमर्पण करना होगा। अतः अपील स्वीकार की जाती है

ए के टी

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।